RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 10 AUGUST 2022 TO 16 AUGUST 2022 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 48 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

व्हॉट्सएप पर अब नहीं ले पाएंगे 'व्यू वंस मेसेज' का स्क्रीनशॉट, नए फीचर की तैयारी Page 3

उड़ान से पहले एयरलाइंस के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का ब्योरा सीमा-शुल्क को देना हुआ जरूरी Page 4

रॉयल एनफील्ड ने नया और स्टाइलिश हंटर 350 लॉन्च किया Page 7

editoria!

निर्यात पर जोर

वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 420 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं तथा 254 अरब डॉलर मूल्य की सेवाओं का रिकॉर्ड निर्यात किया था. लगातार बढ़ते निर्यात से यह इंगित होता है कि भारत में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रति अंतरराष्ट्रीय बाजार में भरोसा बढ़ रहा है. लेकिन निर्यात के साथ-साथ आयात में बढ़ोतरी चिंता की बात है, जिसके कारण व्यापार घाटा और चालू खाते का घाटा बढ़ता जा रहा है. वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) में ही व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है. इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यों से निर्यात बढ़ाने का आह्वान महत्वपूर्ण है. उन्होंने स्थानीय उत्पादों के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा है, ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके. उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के प्रारंभिक दौर में ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारतीय उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया था. बड़ी आबादी होने के कारण भारतीय बाजार का आकार भी बहुत बड़ा है. अगर हम स्थानीय उत्पादों का उपभोग करें, तो उत्पादन भी बढ़ेगा और रोजगार व आमदनी के अधिक अवसर भी पैदा होंगे. साथ ही, हम कई वस्तुओं के आयात को कम कर व्यापार घाटे को भी कम कर सकते है. निर्यात बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक पहलें की गयी हैं, जिनमें दो कार्यक्रम- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआइ स्कीम) तथा कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए किसान व निर्यातकों के बीच संपर्क अभियान- विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं. पीएलआइ स्कीम के तहत वैश्विक स्तर के गुणवत्तापूर्ण निर्यात के लिए उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसमें उत्पादकों को वित्तीय और तकनीकी सहयोग मुहैया कराया जा रहा है. कृषि उत्पादों के निर्यात में लगातार बढ़त है. इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से जिला स्तर के अधिकारियों के सहयोग से किसानों से निर्यातकों का संपर्क कराने की प्रक्रिया चला रही है. एक बड़ी समस्या यह है कि राज्यों के अधिकारी तथा उत्पादकों को निर्यात प्रक्रिया के बारे कम जानकारी होती है. ऐसी कमियों को दूर किया जाना चाहिए. निर्यात पर बल देने के प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह का महत्व इसलिए भी है कि अगर निर्यात के लायक अच्छी गुणवत्ता के वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है, तो घरेलू उपभोक्ताओं को भी बेहतर चीजें उपलब्ध होंगी. प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी रेखांकित किया है कि अगर उत्पादन और निर्यात में वृद्धि होती है, तो अधिक राजस्व संग्रहण भी हो सकेगा. अगले वर्ष भारत को जी-20 समूह की अध्यक्षता मिलेगी. उन्होंने राज्यों को इस मौके का अधिकाधिक लाभ उठाने की सलाह भी दी. इस समूह के देश दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और उनके साथ गहरे व्यापारिक संबंध राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ राज्यों के लिए भी लाभकारी होंगे. आशा है कि राज्य सरकारें प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर अमल कर निर्यात बढ़ाने को प्राथमिकता देंगी.

विदेशी मार्केट में गिरे कच्चे तेल के दाम, क्या भारत में भी सस्ता होगा पेट्रोल

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत में तेलों के दाम कई दिनों से स्थिर बने हुए हैं, लेकिन लोगों को इसमें कमी की उम्मीद लगी है। हालांकि सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों का बिजनेस देखें तो दाम में बड़ी कमी की संभावना नहीं दिखती। सरकारी कंपनियों को भारी घाटा उठाना पड़ा है। विदेशी बाजारों में कच्चे तेल के दाम गिरे हैं। इसे मंदी का असर कहा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका सहित बड़ी आर्थिक महाशक्तियां मंदी का गुणा-भाग लगा रही हैं और पेट्रो पदार्थों की खपत कम कर रही हैं। लिहाजा मांग कम होने से दाम भी गिरे हैं. कच्चे तेल के दाम घटने की एक और वजह है। इंडस्ट्री का आंकड़ा कहता है कि पिछले हफ्ते अमेरिकी कच्चा तेल बहुत अधिक जमा हो गया जिससे पता चलता है कि मांग में भारी कमी है। इससे तेल के दाम गिरे हैं. इस गिरावट का असर दुनिया के अन्य देशों में भी दिख सकता है जहां तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। हालांकि भारत में कई महीने से दाम स्थिर हैं, लेकिन पहले की तुलना में ऊंचाई बनी हुई है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस क्रूड स्टॉक 5 अगस्त के बीते हफ्ते में 2.2 लाख बैरल तक बढ़ गया। यह आंकड़ा अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की ओर से जारी किया गया है। इस बीच ब्रेंट क्रूड वायदा 6 सेंट गिरकर 96.25 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 16 सेंट की गिरावट के साथ 90.34 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। मंगलवार को तेलों के दाम में इसलिए भी हल्की गिरावट देखी गई क्योंकि तेल निर्यात से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। इसमें कहा गया कि रूस से यूरोप के डूजबा तक जाने वाली पाइपलाइन से सप्लाई को सस्पेंड कर दिया गया जो कि यूक्रेन से गुजरती है। अगर यह स्थिति बनी रही तो दाम में कुछ उछाल देखा जा सकता है।

रूस ने रोकी यूरोप की सप्लाई

यूरोप जाने वाली इस तेल सप्लाई को रूस ने इसलिए रोका है क्योंकि उसपर कई पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध चस्पा किया है। यह लाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है। प्रतिबंधों के चलते रूस को तेल का पैसा नहीं मिल रहा। इस वजह से सप्लाई रुक गई है। रूस के इस कदम से मध्य यूरोप में तेलों की सप्लाई बाधित होगी और दाम में वृद्धि देखी जा सकती है। यूरोप और रूस में गैसों की खरीद-बिक्री को लेकर पहले से विवाद चला आ रहा है और इस कड़ी में तेल सप्लाई बाधित होने के नया मामला भी जुड़ गया है।

भारत में क्या स्थिति

भारत में तेलों के दाम कई दिनों से स्थिर बने हुए हैं, लेकिन लोगों को इसमें कमी की उम्मीद लगी है। हालांकि सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों का बिजनेस देखें तो दाम में बड़ी कमी की संभावना नहीं दिखती। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनियों के लागत मूल्य बढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखने की वजह से कुल 18,480 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। सरकारी क्षेत्र की तीन तेल कंपनियों के मुताबिक, अप्रैल-जून तिमाही में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाने की वजह से उनका घाटा काफी बढ़ गया। ऐसा उनकी मार्जिन में गिरावट आने के कारण हुआ।

तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रतिदिन बदलाव करने का अधिकार मिला हुआ है लेकिन बढ़ती खुदरा महंगाई के दबाव में चार महीने से पेट्रोलियम उत्पादों के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें बढ़ने से इन कंपनियों की लागत भी बढ़ गई। इन कंपनियों ने रसोई गैस की एलपीजी दरों को भी लागत के अनुसार नहीं बदला है। अब देखने वाली बात होगी कि तेलों के दाम घटते हैं या कंपनियों के घाटे को पाटने के लिए सरकार इसी दाम पर पेट्रोल-डीजल बेचने की अनुमति देगी।

गांधीनगर में 18 से 22 अक्टूबर तक होगा डिफेंस एक्सपो का आयोजन

नयी दिल्ली। एजेंसी

डिफेंस एक्सपो का आयोजन इस साल 18 से 22 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में यह जानकारी देते हुए बताया कि इस साल का डेफएक्सपो प्रतिष्ठित द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण होगा। इससे पहले डिफेंस एक्सपो का आयोजन 10 से 14 मार्च के बीच में गांधीनगर में ही किया जाना था। हालांकि, मंत्रालय ने चार मार्च यह कहते हुए कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था कि प्रतिभागियों को लॉजिस्टिक से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

मंत्रालय ने कहा कि पांच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच गांधीनगर में होगा। इसमें तीन व्यावसायिक दिवस होंगे। वहीं दो दिन यह प्रदर्शनी आम जनता के लिए खुलेगी। मंत्रालय ने कहा, "सशस्त्र बलों, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (डीपीएसयू) और उद्योग द्वारा उपकरणों और कौशल श्रृंखला का सीधा प्रदर्शन साबरमती रिवर फ्रंट पर पांचों दिन किया जाएगा।" बयान में कहा गया कि डेफएक्सपो-2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और निर्यात में पांच अरब डॉलर का आंकड़ा हासिल करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

सार्वजनिक तेल कंपनियों को पेट्रोल-डीजल कीमतें नहीं बढ़ने से कुल 18,480 करोड़ रुपये का नुकसान

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लागत मूल्य बढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखने की वजह से कुल 18,480 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है।सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों की तरफ से शेयर बाजारों को दी गई जानकारी के मुताबिक, अप्रैल-जून तिमाही में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाने की वजह से उनका घाटा काफी बढ़ गया। ऐसा उनके विपणन मार्जिन में गिरावट आने के कारण हुआ। पेट्रोल-डीजल के अलावा घरेलू एलपीजी के विपणन मार्जिन में कमी आने से इन पेट्रोलियम कंपनियों को बीती तिमाही में हुआ तगड़ा रिफाइनिंग मार्जिन भी घाटे में जाने से नहीं बचा पाया।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को लागत के अनुरूप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रतिदिन बदलाव करने का अधिकार मिला हुआ है लेकिन बढ़ती खुदरा मुद्रास्फीति के दबाव में चार महीने से पेट्रोलियम उत्पादों के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें बढ़ने से इन कंपनियों की लागत भी बढ़ गई। इन कंपनियों ने रसोई गैस की एलपीजी दरों को भी लागत के अनुरूप नहीं बदला है।

आईओसी ने गत 29 जुलाई को कहा था कि अप्रैल-जून तिमाही में उसे 1,995.3 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ। एचपीसीएल ने भी गत शनिवार को इस तिमाही में रिकॉर्ड 10,196.94 करोड़ रुपये का घाटा होने की सूचना दी जो उसका किसी भी तिमाही में हुआ सर्वाधिक घाटा है। इसी तरह बीपीसीएल ने भी 6,290.8 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है। इस तरह इन तीनों सार्वजनिक पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को एक तिमाही में मिलकर कुल 18,480.27 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जो किसी भी तिमाही के लिए अब तक का रिकॉर्ड है।

दरअसल आलोच्य तिमाही में आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने बढ़ती लागत के अनुरूप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन नहीं किया ताकि सरकार को सात प्रतिशत से अधिक चल रही मुद्रास्फीति पर काबू पाने में मदद मिल सके। पहली तिमाही में कच्चे तेल का आयात औसतन 109 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के भाव पर किया गया था। हालांकि खुदरा बिक्री की दरों को लगभग 85-86 डॉलर प्रति बैरल की लागत के हिसाब से समायोजित किया गया था। इस तरह तेल कंपनियों को प्रति बैरल कच्चे तेल पर करीब 23-24 डॉलर का नुकसान खुद उठाना पड़ा।

आम तौर पर तेल कंपनियां आयात समरूपता दरों के आधार पर शोधित तेल कीमत की गणना करती हैं। लेकिन अगर विपणन खंड इसे आयात समरूपता दर से कम दाम पर बेचता है तो कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि सरकार ने कहा है कि तेल कंपनियां खुदरा कीमतों में संशोधन के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन गत छह अप्रैल से अब तक खुदरा बिक्री दरों में कोई बदलाव नहीं किए जाने की ठोस वजह सरकार नहीं बता पाई है।

एक पहलू तो यह है कि राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण चुनावों से पहले तेल कीमतों को स्थिर रखा गया है। इन तीनों कंपनियों ने पिछले साल उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले दरों में संशोधन करना बंद कर दिया था। वह दौर 137 दिनों तक चला था और अप्रैल के पहले हफ्ते के बाद से फिर से चालू है। हालांकि सरकार ने मई में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की थी लेकिन उसका लाभ खुदरा उपभोक्ताओं को मिला था। उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण हुई कमी को छोड़कर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर मौजूदा रोक अब 123 दिन पुरानी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पिछले महीने एक रिपोर्ट में कहा था कि आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने पेट्रोल और डीजल को 12-14 रुपये प्रति लीटर के नुकसान पर बेचा जिससे तिमाही के दौरान उनका राजस्व प्रभावित हुआ।

लागू हो सकता है ईरान परमाणु समझौता, गिर जाएंगी कच्चे तेल की कीमतें

नई दिल्ली। एजेंसी

कच्चे तेल की कीमतों में मंगलवार को करीब एक डॉलर प्रति बैरल से अधिक की गिरावट आई। बीते हफ्ते यह कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया था। साल 2015 के ईरान परमाणु समझौते (Iran Nuclear Deal) को दोबारा शुरू करने के लिए वार्ता में नई प्रोग्रेस के चलते यह गिरावट आई है। इस समझौते को फिर से लागू करने के लिए यूरोपीय संघ ने एक अंतिम मसौदा तैयार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, अगर संबंधित पक्षों को कोई आपत्ति नहीं हुई, तो यह समझौता बहाल हो जाएगा। इस समझौते के बहाल होने से ईरान खुलकर अपने कच्चे तेल का निर्यात कर पाएगा। ऐसा होने पर कच्चे तेल की कीमतों में आगे भी गिरावट आ सकती है। इसका सीधा असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ेगा।

ये हैं क्रूड ऑयल के दाम

ब्रेंट क्रूड मंगलवार को 1.4 फीसदी या 1.34 डॉलर गिरकर 95.31 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं, डबल्यूटीआई क्रूड ऑयल (WTI Crude) 1.4 फीसदी या 1.25 डॉलर गिरकर 89.51 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं, देश की बात करें, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों (Petrol-Diesel Prices) में बुधवार को भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्रूड ऑयल की उच्च कीमतों से घरेलू तेल कंपनियों को पिछली तिमाही में भारी घाटा हुआ है। अब क्रूड ऑयल के दाम घटने से कंपनियां थोड़ी राहत ले सकती हैं।

जानिए बड़े महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

दिल्ली में पेट्रोल का दाम 96.72 रुपये और डीजल का दाम 89.62 रुपये प्रति लीटर पर बना हुआ है। मायानगरी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में बुधवार को पेट्रोल 106.03 रुपये में मिल रहा है और डीजल 92.76 रुपये में मिल रहा है। वहीं, चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.24 रुपये प्रति लीटर है।

इन राज्यों में भी नहीं बदले भाव

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के गुरुग्राम में पेट्रोल का भाव 97.18 रुपये और डीजल का भाव 90.05 रुपये प्रति लीटर पर है। नोएडा में पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.96 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। उधर चंडीगढ़ में पेट्रोल 96.20 रुपये और डीजल 84.26 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल का भाव 96.57 रुपये और डीजल का दाम 89.76 रुपये प्रति लीटर पर है।

बैंको का एमएसएमई ऋण वितरण दोगुना, मौजूदा ग्राहकों को ही कर्ज देने पर अधिक जोरः रिपोर्ट

मुंबई। एजेंसी

कोविड-19 महामारी-पूर्व के स्तर की तुलना में बैंकों का छोटे कारोबारियों को ऋण वितरण दोगुना हो गया है। बैंक हालांकि सतर्क बने हुए हैं और मौजूदा ग्राहकों को ऋण देने पर जोर दे रहे हैं। ऋण से जुड़े आंकड़ों को एकत्र और विश्लेषण करने वाली कंपनी ट्रांसयूनियन सिबिल की रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) से ऋण की मांग वित्त वर्ष 2021-22 में महामारी-पूर्व स्तर के मुकाबले 1.6 गुना थी। रिपोर्ट के अनुसार, मार्च, 2022 तक कुल सक्रिय एमएसएमई उधारकर्ताओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में छह प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 70 लाख रही। रिपोर्ट में कहा गया है, ''कुल एमएसएमई कर्जदारों की वृद्धि में कमी आई है क्योंकि ऋणदाता मौजूदा ग्राहकों को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।'' छोटे व्यवसायों को ऋण देना दरअसल एक नीतिगत उद्देश्य है। रिपोर्ट के अनुसार, एमएसएमई को ऋण का वितरण महामारी पूर्व-स्तर की तुलना में दोगुना हो गया है, जो दर्शाता है कि ऋणदाता बढ़ती कर्ज मांग का समर्थन करने की स्थिति में हैं। वहीं, बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 31 मार्च, 2022 तक 12.8 प्रतिशत पर थीं।

सरकार ने राशन कार्ड जारी करने के लिए वेब आधारित पंजीकरण सुविधा शुरू की

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड जारी करने के लिए एक साझा पंजीकरण सुविधा की शुरुआत की है। इस पंजीकरण का उद्देश्य बेघर लोगों, निराश्रितों, प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए अधिकतम कवरेज प्रदान करता है। वर्तमान में इस अधिनियम के तहत लगभग 79.77 करोड़ लोगों को अत्यधिक रियायत आधार पर खाद्यान्न दिया जाता है। इस हिसाब से 1.58 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि 'सामान्य पंजीकरण सुविधा' (माई राशन-माई राइट) का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पात्र लाभार्थियों की शीघ्र पहचान करना है। साथ ही इस तरह के लोगों की राशन कार्ड जारी करने में मदद करना है, ताकि वे एनएफएसए के तहत पात्रता का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि पिछले सात से आठ वर्षों में अनुमानित 18 से 19 करोड़ लाभार्थियों से जुड़े लगभग 4.7 करोड़ राशन कार्ड विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पात्र लाभार्थियों को नियमित आधार पर नए कार्ड भी जारी किए जाते हैं। सचिव ने बताया कि शुरुआत में वेब आधारित नयी सुविधा 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट आधार पर उपलब्ध होगी। इस महीने के अंत तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुरू कर दिया जाएगा। सचिव के अनुसार, इन 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश असम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब और उत्तराखंड शामिल हैं।

क्या अब किराये पर रहने के लिए देना होगा 18 फीसदी टैक्स

नई दिल्ली। एजेंसी

जीएसटी काउंसिल की हाल में हुई बैठक में जीएसटी नियमों में कई बदलाव किए गए थे। ये बदलाव 18 जुलाई से लागू हो गए हैं। इनमें घर के किराए पर जीएसटी (उएऊ दह प्दलें ंिहू) से जुड़ा नियम भी शामिल है। हालांकि किराए पर टैक्स कुछ खास परिस्थितियों में ही लगेगा। अगर आप नौकरी करते हैं और आपने कोई फ्लैट किराए पर ले रखा है तो आपको किराए पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहां हम आपको बता रहे हैं कि जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) में किराए पर किसे टैक्स देना होगा।

जैसा कि 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में सिफारिश की गई थी, किरायेदार को रिवर्स चार्ज बेसिस (RCM) पर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना चाहिए. हालांकि, वे इस मूल्य को कटौती के रूप में दावा कर सकते हैं, जबकि वे जीएसटी रिटर्न में बिक्री पर कर का भुगतान करते हैं। नए नियमों के तहत अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन (नौकरीपेशा आदमी या छोटा कारोबारी) अपना फ्लैट जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड पर्सन (उदाहरण के लिए कोई कंपनी) को देता है तो किराए पर जीएसटी लगेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत किराएदार को किराए पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। अगर किराएदार जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू नहीं होगा। किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा कर्मचारी के रहने, गेस्ट हाउस या दफ्तर के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आवासीय प्रॉपर्टी पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। उदाहरण के लिए, कोई कर्मचारी या कंपनी जो अपने दफ्तर के लिए अपार्टमेंट किराये पर ले रही है, उसे किराये पर जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। जीएसटी का भुगतान किरायेदार करेगा। अगर किसी कंपनी ने अपने कर्मचारी के लिए आवासीय फ्लैट लिया है और मकान मालिक जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी जीएसटी का भुगतान कंपनी को करना होगा. अगर मकान मालिक और किराएदार दोनों जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं तो इस मामले में किराए पर टैक्स का नया नियम लागू नहीं होगा।

व्हॉट्सएप पर अब नहीं ले पाएंगे 'व्यू वंस मेसेज' का स्क्रीनशॉट, नए फीचर की तैयारी

नयी दिल्ली। एजेंसी

व्हॉट्सएप एक बार नजर आने वाले 'व्यू वन्स मेसेज' का स्क्रीनशॉट लेने पर रोक लगाने जा रही है। इसके लिए त्वरित संदेश सेवा कंपनी जल्द एक नया फीचर लेकर आने वाली है। मेटा के स्वामित्व वाली व्हॉट्सएप ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि नया फीचर आने के बाद 'व्यू वन्स मेसेज' श्रेणी वाले संदेशों का अब कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। इस तरह के संदेश पाने वाला व्यक्ति जब उसे एक बार पढ़ लेता है तो वह संदेश अपने-आप अदृश्य हो जाता है। मेटा के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने व्हॉट्सएप पर यह नया फीचर लाने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे उपयोगकर्ता की निजता को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। जुकरबर्ग ने कहा, "व्हॉट्सएप निजता से जुड़े कुछ नए फीचर लेकर आ

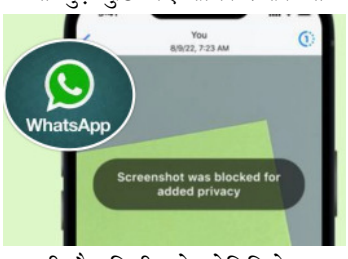

रही है। किसी को नोटिफिकेशन मिले बगैर ग्रुप चैट से बाहर निकलने की सुविधा और उपयोगकर्ता को यह नियंत्रण देना कि वह अपने ऑनलाइन होने के बारे में किसे जानकारी देना चाहता है। इसके अलावा व्यू वंस मेसेज का स्क्रीनशॉट लेने पर रोक लगाने का फीचर भी लाया जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि व्हॉट्सएप उपयोगकर्ताओं के संदेशों को सुरक्षित एवं निजी रखने के लिए नए तरीके लाने की दिशा में काम करती रहेगी। इस तरह आमने-सामने होने वाली बातचीत की तरह व्हॉट्सएप चैट को भी सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। व्हॉट्सएप ने 'व्यू वंस मेसेज' सुविधा हाल ही में शुरू की है जिसके जरिये संदेश को सिर्फ एक बार ही पढ़ा जा सकता है और उसके बाद वह अपने-आप गायब हो जाता है। इस तरह उपयोगकर्ताओं को यह विकल्प मिलता है कि उसके भेजे गए संदेश का कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं रख सकता है। लेकिन ऐसे संदेशों का भी स्क्रीनशॉट लेने की कुछ शिकायतें मिलने के बाद व्हॉट्सएप ने अब इसमें सुधार करने के लिए नया फीचर लाने की तैयारी की है। मेटा के बयान के मुताबिक, "अब व्हॉट्सएप अतिरिक्त सुरक्षा के लिए व्यू वंस मेसेज का स्क्रीनशॉट लेने से रोक लगाने की व्यवस्था कर रहा है। इस फीचर का परीक्षण चल रहा है और जल्द ही उपयोगकर्ताओं के लिए इसे जारी कर दिया जाएगा।" इसके साथ ही व्हॉट्सएप इस महीने यह सुविधा भी लेकर आने वाली है जिसमें उपयोगकर्ताओं को यह तय करने का अधिकार होगा कि कौन उन्हें ऑनलाइन होने पर देख सकता है। इसके अलावा ग्रुप चैट में शामिल अन्य उपयोगकर्ताओं को पता चले बगैर उस ग्रुप से निकलने का फीचर भी लाने की तैयारी है।

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे चढ़कर 79.52 पर पहुंचा

मुंबई। एजेंसी

विदेशी मुद्रा की आवक और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने से रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे मजबूत होकर 79.52 के स्तर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 79.59 पर खुला और शुरुआती सौदों में बढ़त दर्ज करते हुए 79.52 के स्तर को छू गया। इस तरह रुपये ने पिछले बंद भाव के मुकाबले 11 पैसे की बढ़त दर्ज की।

पिछले सत्र में, सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 79.63 पर बंद हुआ था। घरेलू शेयर बाजार और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार मंगलवार को मुहर्रम की वजह से बंद थे। इसबीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.10 प्रतिशत गिरकर 106.26 पर आ गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.27 प्रतिशत गिरकर 96.05 डॉलर प्रति बैरल पर था।

नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग भी बैन

हिमाचल में नए साल से इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे ये बैग, नोटिफकेशन जारी

शिमला। एजेंसी

हिमाचल में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के बाद राज्य सरकार नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग पर भी नए साल यानि 1 जनवरी, 2023 से बैन लगाने जा रही है। यानि नए साल से हिमाचल में 60 उएश से अधिक मोटाई वाले नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा।

पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी की है। यह नोटिफिकेशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी की गई। सरकार ने थोक व्यापारियों, होलसेलर, दुकानदारों और वेंडरों को को ऑफ नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग का स्टॉक निकालने के लिए 4 महीने का समय दिया है। 1 जनवरी के बाद इसका प्रयोग, भंडारण और बेचने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने पहली जुलाई में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने के समय 60 उएश से कम मोटाई वाले नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया था लेकिन इसके अधिक अच्छे परिणाम नहीं आए। लोग बेहिचक 60 उएश से अधिक मोटाई वाले नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसी वजह से अब हिमाचल को नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग मुक्त बनाने का फैसला लिया गया है।

कपड़े की तरह दिखने वाले नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग को सेहत के लिए खतरनाक मानते हुए विभाग ने इसे बैन करने का निर्णय लिया है। प्लास्टिक को पॉलीप्रोपाइलीन से बनाया जाता है। राज्य की लगभग सभी दुकानों पर यह नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग कपड़े के बैग के नाम पर उपयोग किया जा रहा है।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार पॉलीप्रोपाइलीन को प्लास्टिक की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत पॉलीप्रोपाइलीन फाइबर से बने बैग को पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। लेकिन दुकानदार और उत्पादक यह कह कर बेच रहे हैं कि वह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है।

सबसे पहले 1999 में बैन हुआ प्लास्टिक

हिमाचल में सबसे पहले जनवरी 1999 में रंगदार पॉलीथीन लिफाफों पर बैन लगाया गया था। उसके बाद जून 2004 को 70 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन के थैलों पर प्रतिबंध लगाने वाला हिमाचल पहला राज्य बना। 2 अक्टूबर 2009 को पॉलीथीन थैलों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई और इसकी जगह कपड़े की तरह दिखने वाले नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किए जाने लगे। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध के बाद अब इसे भी बैन करने का फैसला लिया गया है।

डिजिटल लिटरेसी में भारत के 2.5 मिलियन सिविल सर्वेन्ट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए

माइक्रोसॉफ्ट ने एमएसडीई और सीबीसी के साथ साझेदारी की

प्रोजेक्ट का उद्देश्य 2.5 मिलियन सिविल सर्वेन्ट्स की फंक्शनल कंप्यूटर लिटरेसी बढ़ाना

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के सिविल सर्वेन्ट्स को फ्यूचर-रेडी स्किल्स के साथ सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन (सीबीसी) के साथ भागीदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल प्रोडक्टिविटी स्किल्स में एमएसडीई द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग - प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत सरकार के लगभग 2.5 मिलियन सिविल सर्वेन्ट्स की फंक्शनल कंप्यूटर लिटरेसी को बढ़ाना है। यह प्रोजक्ट समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को कुशल और प्रभावी सिटीज़न सेन्ट्रिक सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगा। यह उन्हें अंतिम छोर तक सामाजिक कल्याण की सेवाएं देने में सक्षम बनाएगा।

श्री राजेश अग्रवाल, सेक्रेटरी एमएसडीई; श्री आदिल जैनुलभाई, चेयरमैन, सीबीसी; श्री प्रवीण परदेशी, मैम्बर एडमिन, सीबीसी और श्री आशुतोष चड्ढा, ग्रुप हेड एंड डायरेक्टर, गवर्नमेन्ट अफेयर्स, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की उपस्थिति में इस एमओयू को साइन और एक्सचेन्ज किया गया।

प्रोजेक्ट के भीतर, प्रशिक्षण में सेक्शन ऑफिसर्स, असिस्टेन्ट सेक्सन ऑफिसर्स, क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, और केंद्र सरकार की संस्थाओं में सीनियर, जूनियर और सहायक स्तरों पर समकक्ष ऑफिसर्स जैसे जॉब रोल्स शामिल होंगे। सीबीसी ने रक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता, व्यय, वित्त, सामाजिक न्याय, नागरिक उड्डयन, पोर्ट्स और शिपिंग, और श्रम मंत्रालयों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग योजनाएं शुरू की हैं। इन जॉब रोल्से के बीच पहचाने गए प्रमुख कॉम्पीटैन्सी गैप्स में से एक पेशेवर स्तर पर वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स पर काम करते समय आवश्यक डिजिटल प्रोडक्टिविटी एप्लिकेशन्स स्किल्स की कमी थी। इसलिए, साझेदारी के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों को उनके डिजिटल प्रोडक्टिविटी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए सक्षम किया जाएगा ताकि वे विभिन्न मंत्रालयों में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।

साझेदारी की सराहना करते हुए, एमएसडीई के सेक्रेटरी, श्री राजेश अग्रवाल ने कहा, 'आज का सहयोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित मिशन कर्मयोगी पहल के अनुरूप है, यह हमारे सिविल सर्वेन्ट्स के विकास की दिशा में है। डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों पर जोर देकर, हम अपने नागरिकों को परेशानी से मुक्त सेवाएं प्रदान करने और दिन-प्रतिदिन के बिजनेस में पारदर्शिता लाने में सक्षम होंगे। हमारा उद्देश्य नागरिकों के अनुकूल और बिजनेस के अनुकूल नीतियां विकसित करना है। टेक्नोलॉजी हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पॉवरपॉइंट अब हमारे कामकाजी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि हमारे वर्कफोर्स को इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाए, और मुझे विश्वास है कि इस गठबंधन के साथ, हम मिशन कर्मयोगी को एक सफल योजना बनाने में सक्षम होंगे'।

सीबीसी के चेयरमैन श्री आदिल ज़ैनुलभाई ने कहा, 'माननीय प्रधानमंत्री का मिशन कर्मयोगी का विज़न प्रत्येक सिविल सर्वेन्ट की क्षमता को मजबूत करना है। उन प्रमुख क्षमताओं में से एक दिन-प्रतिदिन के काम के लिए विभिन्न प्रकार की डिजिटल टेक्नोलॉजी में सक्षम होना है। एमएसडीई और माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग से सिविल सर्वेन्ट्स को अपनी पसंद के समय पर डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने की अनुमति मिलेगी। यह उनकी क्षमताओं को बढ़ाएगा और उन्हें और अधिक प्रभावी बनाएगा।'

मेडिकल टूरिज्म को मिलेगा बूस्ट

विदेशी मरीजों की मदद के लिए 10 एयरपोर्ट्स पर तैनात होंगे दुभाषिए

नई दिल्ली। एजेंसी

विदेशों की तुलना में भारत में इलाज काफी सस्ता है। यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में विदेशों से लोग इलाज कराने भारत आते हैं। इसे मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है। देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत देश के दस हवाई अड्डों पर दुभाषिए, विशेष डेस्क, एक बहुभाषी पोर्टल और वीजा नियमों को सरल बनाया जाएगा। यह मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार की हील इन इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 अगस्त को इस पहल की घोषणा कर सकते हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय विदेशी मरीजों की सुगमता के लिए इसके विभिन्न पहलुओं और उपायों को अंतिम रूप दे रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार ने 44 देशों की पहचान की है जहां से बड़ी संख्या में लोग चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भारत आते हैं, इन देशों में इलाज की लागत और क्वालिटी को भी ध्यान में रखा गया है। उन्होंने बताया कि ये मुख्य रूप से अफ्रीकी, लातिन अमेरिकी, सार्क और खाड़ी देश हैं। सूत्रों ने कहा कि 10 चिन्हित हवाई अड्डों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, विशाखापत्तनम, कोच्चि, अहमदाबाद, हैदराबाद और गुवाहाटी में इन 44 देशों के मरीजों की संख्या ज्यादा है।

उड़ान से पहले एयरलाइंस के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का ब्योरा सीमा-शुल्क को देना हुआ जरूरी

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने विमानन कंपनियों से उड़ानों के प्रस्थान से 24 घंटे पहले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के संपर्क, पीएनआर विवरण और भुगतान से जुड़ी जानकारी सीमा-शुल्क अधिकारियों के साथ साझा करने को कहा है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यात्रियों के विवरण से मिलने वाली सूचना का इस्तेमाल देश में आने वाले या देश से बाहर जाने वाले यात्रियों की निगरानी में सुधार और जोखिम मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सोमवार को 'यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियम, 2022' को अधिसूचित करते हुए विमानन कंपनियों को अनिवार्य रूप से इसका अनुपालन करने को कहा है।

इस विनियम का उद्देश्य यात्रियों का "जोखिम विश्लेषण" करना है ताकि आर्थिक और अन्य अपराधियों को देश छोड़कर भागने से रोका जा सके। इसके साथ ही इस प्रावधान से तस्करी जैसे किसी भी अवैध गतिविधियों की जांच करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही भारत अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के पीएनआर का ब्योरा इकट्ठा करने वाले 60 देशों की सूची में शामिल हो गया है। अधिसूचना के मुताबिक, "प्रत्येक एयरलाइन यात्रियों के नाम एवं अन्य रिकॉर्ड की जानकारी सीमा-शुल्क विभाग को देगा। परिचालक यह जानकारी सामान्य कारोबारी परिचालन के तहत पहले ही इकट्ठा कर चुके हैं।" अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक विमानन कंपनी को इस नियम के अनुपालन के लिए सीमा शुल्क विभाग के पास पंजीकरण कराना होगा। विमानन कंपनियों को भारत आने वाले और भारत से जाने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सूचना देनी होगी। इस सूचना में यात्री का नाम, बिलिंग / भुगतान जानकारी (क्रेडिट कार्ड नंबर), टिकट जारी करने की तारीख के साथ एक ही पीएनआर टिकट पर यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम भी शामिल होंगे।

सरकार ने उड़ान के 24 घंटे पहले अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के पीएनआर की जानकारियां सीमा-शुल्क विभाग को देने का प्रस्ताव पांच साल पहले के बजट में ही रखा था। लेकिन इसका औपचारिक ढांचा अब जाकर सामने आ पाया है। हालांकि, सरकार ने इस तरह की व्यवस्था को जरूरी करने के पीछे की वजह नहीं बताई है। लेकिन विश्लेषकों ने कहा कि यह प्रावधान बैंकों का कर्ज न चुकाने वाले कर्जदारों को देश छोड़कर भागने से रोकना है।

सरकार खुद संसद में कह चुकी है कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे कुल 38 आर्थिक अपराधी पिछले पांच वर्षों में देश से भाग चुके हैं।

इस अधिसूचना के मुताबिक, इस नियम का पालन नहीं करने पर एयरलाइन को हर उल्लंघन पर न्यूनतम 25,000 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अन्य कानूनी एजेंसियों को भी यात्रियों से जुड़ी जानकारी साझा की जा सकेगी। हालांकि, इस तरह का कदम मामले को देखकर उठाया जाएगा।

एमेज़ॉन इंडिया ने एंट्रप्रेन्योर्स को अपना लॉजिस्टिक्स बिज़नेस स्थापित करने में मदद करने के लिए एक स्पेशल डाईवर्सिटी ग्रांट प्रदान की

डिलीवरी सर्विस पार्टनर प्रोग्राम में महिलाओं, दिव्यांगों और एलजीबीटीक्यूआईएक्ष समुदाय की प्रतिभागिता को बढ़ाना

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

अपने डिलीवरी सर्विस पार्टनर (डीएसपी) कार्यक्रम में वंचित समुदायों के उद्यमियों को शामिल करने के लिए आज एमेज़ॉन ने एक विशेष अनुदान की घोषणा की। इस डीएसपी कार्यक्रम के तहत एमेज़ॉन द्वारा ऐसे उद्यमियों को जो एमेज़ॉन में डिलीवरी सर्विस पार्टनर बनने के इच्छुक हैं, उन्हें एमेज़ॉन की शानदार डिलीवरी तकनीक, डिलीवरी के व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा पेरोल सर्विसेज सेवाएं जैसे कि पेरोल प्रबंधन, इंश्योरेंस, रिक्रूटमेंट तकनीकी आदि जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक ऐसी मजबूत टीम का निर्माण करना एक कठिन चुनौती होती है जो अपने समुदाय को अच्छे से समझ सके, हांलाकि छोटे व्यवसाय के मालिक ऐसा करने में अक्सर सफल रहते हैं। विभिन्न अनुदान कार्यक्रमों के माध्यम से सैकड़ों उद्यमियों का समर्थन करने के लिए एमेज़ॉन ने 7 मिलीयन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जाहिर की है। महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों तथा एलजीबीटीक्यूआइए समुदाय से आने वाले उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने हेतु स्टार्टअप की लागत को कवर करने के लिए कंपनी एक विशेष डाइवर्सिटी ग्रांट लेकर आई है जिससे ऐसे समुदाय के उद्यमियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। ऐसे व्यक्ति जिनके पास पहले का कोई भी लॉजिस्टिक एक्सपीरियंस नहीं है वह भी इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर, एमेज़ॉन का लक्ष्य उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करना है तथा वंचित समुदाय के उद्यमियों के रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम करना है जिससे वह अपना बिजनेस सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें।

शराब के प्रीमियम स्टोर ला रहे हैं बदलाव ताकि लोग ज्यादा नहीं, अच्छा पिएं

प्रीमियम लिकर स्टोर्स के बढ़ने से खरीददारों के बर्ताव में बदलाव -रिसर्च

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वैश्विक रिसर्च एजेंसी घ्ह्यएध्य से एक मार्केट सर्वे कराया जिससे की खरीददारों के अनुभव और आला दर्जे के प्रीमियम शराब स्टोर के प्रति दृष्टिकोण की समीक्षा की जा सके। इस सर्वे में दिलचस्प बातें सामने आईं जो लोगों के शराब खरीदने के बदलते अनुभव के बारे में हैं और यह भी पता लगा की देश के प्रमुख क्षेत्रों में प्रीमियमीकरण में इज़ाफा हो रहा है। इस सर्वे में सामने आए जो खास रुझान शराब उद्योग के भविष्य को आकार देंगे उनमें शामिल हैं:

प्रीमियमीकरण के चलते महिलाएं लिकर स्टोर में पहले से ज्यादा संख्या में जा रही हैं। सर्वे में पता लगा की सामान्य स्टोर के आंगतुकों में महिलाओं की तादाद जहां 2 प्रतिशत है वहीं प्रीमियम स्टोर में यह आंकड़ा 10 प्रतिशत है और वहां जाकर अपना पसंदीदा ब्रांड खरीदती हैं। प्रीमियम स्टोर में जो सुविधा एवं सुरक्षा होती है उसकी वजह से यह वृद्धि हो रही है, महिलाएं खुद को स्वतंत्र अनुभव करती हैं और प्रीमियम ब्रांड्स का जायज़ा लेते हुए खरीददारी करती हैं।

प्रीमियम आउटलेट सुरक्षित व बेहतर माहौल मुहैया कराते हैं

सुरक्षित व आमंत्रित करता परिवेश पुरुषों व महिलाओं को प्रोत्साहित करता है की वे प्रीमियम स्टोर में ज्यादा वक्त व्यतीत करें और शॉपिंग का आनंद लें। सर्वे में पता लगा की प्रीमियम स्टोर में 23 प्रतिशत पुरुष किसी के साथ आते हैं और 63 प्रतिशत अकेले, जबकि आम स्टोर पर 27 प्रतिशत पुरुष किसी के साथ व 72 प्रतिशत अकेले आते हैं। दूसरी तरफ, बेहतर परिवेश की वजह से प्रीमियम लिकर स्टोर में 63 प्रतिशत महिलाएं अकेली आती हैं जबकि केवल 37 प्रतिशत किसी के साथ आती हैं। सिर्फ शराब के लिए बल्कि उम्दा अनुभव एवं आज़माईश के लिए आते हैं उपभोक्ता प्रीमियम स्टोर पर 43 प्रतिशत आगंतुक समूह में आते हैं और लिकर स्टोर में विभिन्न उत्पादों का जायज़ा एवं अनुभव लेते हैं। आम शराब स्टोर से अलग प्रीमियम स्टोर ग्राहकों को खूबसूरती से डिजाइन किए गए आउटलेट के भीतर प्रवेश करने देते हैं और वे शैल्फ में रखी शराबों से परिचित होते हुए अपना पसंदीदा पेय खरीद लेते हैं। रिसर्च में पता लगा की 31 से 40 वर्षीय आयु वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रयोगशील हैं और यह ब्राउज़िंग ट्रैंड भी उन्हीं की वजह से बढ़ रहा है। 54 प्रतिशत ग्राहक उत्पादों के बारे में पूछताछ करते हैं। समूह में आने वाले ग्राहक ज्यादा ऐक्सप्लोर करते हैं (43 प्रतिशत), अकेले आने वालों के मामले में यह आंकड़ा 29 प्रतिशत है। यह सर्वे इशारा करता है की जिन ड्रिंक्स में लोग अधिक दिलचस्पी रखते हैं वे हैं- बीयर और रम। नॉन-पीक ऑवर्स में इन्हीं की सबसे अधिक ब्राउजिंग और बातचीत हुई है। सामान्य स्टोर्स के मुकाबले प्रीमियम स्टोर्स में 35 प्रतिशत अधिक खरीददार रिटेलर से बातचीत करते हैं।

जीईएम पोर्टल पर 300 से अधिक सहकारी समितियां खरीदार के रूप में जुड़ीं

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सरकारी ऑनलाइन खरीद पोर्टल जीईएम पर अमूल और इफको समेत 300 से अधिक सहकारी समितियों को खरीदार के रूप में शामिल करने की मंगलवार को घोषणा की। शाह ने ऑनलाइन माध्यम से जीईएम पर सहकारी समितियों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके साथ ही उन्होंने इन सहकारी समितियों से अपने कारोबार के विस्तार के लिए आपूर्तिकर्ताओं के रूप में भी जीईएम पर पंजीकरण कराने को कहा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत एक जून को जीईएम का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सहकारी संस्थाओं को जीईएम पोर्टल से खरीद की अनुमति दी थी। इससे पहले सहकारी समितियों को इस मंच पर 'खरीदार' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति नहीं थी। देश में 8.5 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं जिनसे लगभग 29 करोड़ सदस्य जुड़े हुए हैं। सहकारिता मंत्रालय ने 589 सहकारी समितियों को जीईएम पोर्टल पर मौजूदगी के लिए योग्य पात्र के रूप में चुना है। इनमें से 300 समितियों को जीईएम पर शामिल कर लिया गया।

जीईएम से जुड़ने वाली प्रमुख सहकारी समितियों में इफको, कृभको, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), अमूल और सारस्वत सहकारी बैंक शामिल हैं। जीईएम पर पहले दिन 25 करोड़ रुपये के ऑर्डर दिए जाने की उम्मीद है। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने कहा, 'अब सहकारिता समितियों के लिए जीईएम से खरीदारी के दरवाजे खुल गए हैं।' उन्होंने कहा कि कई राज्यों में सक्रिय 45 सहकारी समितियों समेत 300 से अधिक सहकारी समितियों को जीईएम से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को खरीदार के रूप में पंजीकृत होने के पात्रता मानदंडों में आगे जाकर छूट दी जाएगी। इस मौके पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस पहल से सहकारी समितियों के लिए व्यापार आसान हो जाएगा और इससे काफी बचत होगी। उन्होंने कहा कि सहकारिताओं के पोर्टल से जुड़ने से जीईएम पर व्यापार का मूल्य काफी बढ़ जाएगा।

वहीं, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने इस कदम को सहकारी समितियों के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि इससे उन्हें बड़ी मदद मिलेगी। जीईएम पर सहकारी समितियों की मौजूदगी चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। पहले चरण में 100 करोड़ रुपये के कारोबार वाली सभी पात्र सहकारी समितियां जीईएम पर ऑर्डर देना शुरू कर सकेंगी। एनसीयूआई ने इन सहकारी समितियों की एक सूची तैयार की है और जेम पर इनकी मौजूदगी प्रक्रिया शुरू करने के लिए जीईएम को इसकी जानकारी दे दी है।

सहकारिता मंत्रालय के बयान के अनुसार, अब तक लगभग 61,851 सरकारी खरीदारों और लगभग 48.75 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाताओं ने जीईएम पर पंजीकरण कराया है। उन्होंने 10,000 से अधिक उत्पादों और 288 सेवा श्रेणियों में 45 लाख से अधिक उत्पादों को इस पोर्टल पर सूचीबद्ध किया है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ने से फोर्जिंग, कास्टिंग उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव : एआईएफआई

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की स्वीकार्यता बढ़ने के साथ घरेलू फोर्जिंग और कास्टिंग उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे क्षमता का उपयोग कम हो जाएगा। उद्योग निकाय एआईएफआई ने बुधवार को यह बात कही। एसोसिएशन ऑफ इंडियन फोर्जिंग इंडस्ट्री (एआईएफआई) ने कहा कि यदि सरकार ने सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के बजाय हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहन नहीं दिया, तो बढ़ती उत्पादन लागत से जूझ रहे उद्योग की 60 प्रतिशत तक इकाइयों को अपना परिचालन बंद करना पड़ सकता है। एआईएफआई ने कहा कि कुल घरेलू फोर्जिंग उत्पादन का 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा वाहन उद्योग में इस्तेमाल होता है। निकाय ने कहा कि वाहन क्षेत्र में सुस्ती के बीच फोर्जिंग उद्योग में औसत कुल क्षमता पर 50 प्रतिशत की कमी देखने को मिल रही है। एआईएफआई के अध्यक्ष विकास बजाज ने कहा कि हमारा अनुमान है कि इलेक्ट्रिक वाहन अगले कुछ साल में फोर्जिंग और कास्टिंग उद्योग की 60 प्रतिशत कंपनियों को बंद कर देंगे। इससे क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ेगी और इकाइयां बंद होंगी। एसोसिएशन के मुताबिक, एक पारंपरिक ड्राइवट्रेन में 2,000 घूमने वाले कलपुर्जे होते हैं जबकि इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन में इनकी संख्या मात्र 20 होती है। आईवीसीए द्वारा ईवाई और इंडस लॉ के सहयोग से किए गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण 20212 में सालाना आधार पर 168 प्रतिशत बढ़कर 3,30,000 इकाई पर पहुंच गया है। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि घरेलू ईवी मांग 2027 तक बढ़कर 90 लाख वाहनों तक पहुंच जाएगी।

टाटा के पास आते ही फिरने लगी एयर इंडिया की किस्मत

फिर उड़ान भरेंगे धूल फांक रहे 10 जंबो जेट

नई दिल्ली। एजेंसी

टाटा ग्रुप के हाथों में आते ही एयर इंडिया का कायाकल्प होने लगा है। कंपनी ने रविवार को कहा कि वह संचालन से बाहर चल रहे अपने 10 बड़े विमानों को 2023 की शुरुआत तक सेवा में शामिल करेगी। इन विमानों में बड़ा ईंधन टैंक होता है, जिससे उसे भारत-अमेरिका तथा भारत-कनाडा जैसी लंबी दूरी के अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर उड़ान भरने में आसानी होती है। एयर इंडिया के विशाल विमानों के बेड़े में अभी 43 विमान हैं, जिनमें से 33 संचालन में हैं। यह बड़ा सुधार है क्योंकि एयरलाइन हाल फिलहाल तक 28 विमानों का संचालन कर रही थी। कंपनी ने बताया कि बाकी के विमान 2023 की शुरुआत तक सेवा में वापस लौटेंगे। एयर इंडिया ने साथ ही घोषणा की कि वह दिल्ली और कनाडा में वैंकूवर के बीच 31 अगस्त के बाद से दैनिक उड़ान सेवा शुरू करेगी। अभी वह दिल्ली-वैंकूवर मार्ग पर सप्ताह में तीन उड़ानों का संचालन करती है। उसने कहा कि भारत और कनाडा के बीच बढ़ती आवाजाही को देखते हुए दिल्ली-वैंकूवर मार्ग पर उड़ानों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है। बोइंग टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया को खरीदे जाने के बाद उसके साथ निकटता से काम कर रहा है ताकि उन विमानों को सेवा में शामिल किया जा सकें, जो कोविड-19 महामारी तथा अन्य वजहों से लंबे समय से खड़े हुए हैं।

सात दशक बाद घर वापसी

गौरतलब है कि टाटा समूह ने 27 जनवरी को एयर इंडिया का नियंत्रण अपने हाथ में लिया था। कंपनी की करीब सात दशक बाद टाटा ग्रुप में घर वापसी हुई है।एयर इंडिया के नव नियुक्त सीएमडी कैम्पबेल विल्सन ने रविवार को एक बयान में कहा कि दिल्ली-वैंकूवर मार्ग पर उड़ानों की संख्या में वृद्धि एयर इंडिया के बेड़े तथा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में पहला कदम है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2021-22 में खुदरा क्षेत्र में 30,000 करोड़ रुपये का निवेश किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने खुदरा कारोबार में 30,000 करोड़ रुपये (करीब 3.76 अरब डॉलर) का निवेश किया है। कंपनी ने बीते वित्त वर्ष 2021-22 में 2,500 स्टोर जोड़े हैं, जिससे उसकी दुकानों की संख्या बढ़कर 15,196 पर पहुंच गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने अपने वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि खुदरा कारोबार करने वाली कंपनी रिलायंस रिटेल ने वर्ष के दौरान 1.11 करोड़ वर्ग फुट भंडारण की जगह जोड़ा है और गोदाम स्थान लगभग दोगुना होकर 2.27 करोड़ वर्ग फुट हो गया। कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान 1.50 लाख से अधिक लोगों को काम पर रखा, जिससे इसके कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़कर 3.61 लाख हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस रिटेल ने वर्ष के दौरान उत्पादकों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई), सेवा प्रदाताओं और स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हुए अपने संसाधन परिवेश को और मजबूत किया। आरआईएल ने कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 में 30,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ जैविक विकास, अधिग्रहण और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से क्षमताओं का निर्माण किया है। रिलायंस रिटेल ने वर्ष के दौरान 2,500 से अधिक नए स्टोर और 1.11 करोड़ वर्ग फुट का गोदाम स्थान जोड़ा है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में औसतन प्रति दिन सात स्टोर जोड़े हैं। रिलायंस रिटेल ने अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं और आगे के रणनीति पर कहा कि वह 'नए स्टोर विस्तार' में तेजी लाएगा और डिजिटल कॉमर्स व्यवसाय को बढ़ाने पर जोर देना जारी रखेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कारोबार विकास को सहयोग करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और उत्पाद तथा डिजाइन परिवेश को मजबूत करने के लिए भी काम करेगा।

रक्षा बंधन, 11 अगस्त स्पेशल

भाई-बहन के स्नेहमयी लगाव-जुड़ाव की अभिव्यक्ति का पर्व है रक्षा बंधन। इसे मनाने को लेकर दोनों में भरपूर उत्साह-उमंग होता है। ऐसा हो भी क्यों न, बचपन से लेकर किशोर और युवावस्था तक उनके आपसी स्नेह का बाह्य स्वरूप भले बदलता रहे लेकिन कोमल भावनाओं का आंतरिक बंधन ताउम्र एक समान रहता है।

भाई की कलाई पर बहन के स्नेह का बंधन

अक्षत-रोली, चंदन का टीका, रेशम का धागा और मन में भाई के प्रति प्रेम-स्नेह की हिलोरें! सब साथ लेकर बहनें रक्षा बंधन आते ही निकल पड़ती हैं भाइयों को राखी बांधने। उत्सुकता, उत्साह ऐसा कि दूरी और हर अड़चन को भूल जाती हैं। कोई बीस-तीस किलोमीटर से आती है तो कोई हजार किलोमीटर की यात्रा कर पहुंच जाती है। जिन्हें घर के काम से फुर्सत न मिलती थी, वो ऐसी बेफिक्री ओढ़ लेती हैं, जैसे काम से स्थायी रूप से छुट्टी मिल गई हो। मन में दबी प्रफुल्लता मुख पर छलक-छलक जाती है। कोई पति से मनुहार करने लगता है, 'चलो मायके पहुंचा कर आओ।' कोई उलाहना देता है, 'अब क्या राखी पर भी मायके न पहुंचाओगे?' ऐसी मनुहार, उमंग होना स्वाभाविक है, रक्षा बंधन का पर्व है ही ऐसा।

उधर विवाहित महिलाओं के मायके में भी राखी पर उसके आने के स्वागत की तैयारी शुरू हो जाती है। मांएं बेटियों के स्वागत के लिए पलक-पावड़े बिछा लेती हैं। उनके छूटे कमरों को फिर से सजा दिया जाता है। भाई, बहन के स्नेह में पूए, खीर, सिंवइयां बनवाने लगते हैं। उसके पसंद का कोई व्यंजन रह न जाए, उपहारों में कोई कमी न रह जाए, भाई टोह लेने लगते हैं। जानते हैं, बहनें अभावों को बड़ी कुशलता से छिपा लेने में माहिर होती हैं। उन्हें बिन बोले ही बहन के मन की बात समझनी होती है। भाई चाहते हैं, बहनें आएं तो मायके में जायके के साथ सुख-संतोष, आत्मीयता का आस्वाद भी करती जाएं।

अनूठे रिश्ते की मिठास

राखी के जरिए अभिव्यक्त होने वाला भाई-बहन का रिश्ता, अपने आप में अनूठा और अप्रतिम होता है। समय के साथ इनका स्वरूप बदलता रहता है। बचपन में भाई-बहन के बीच रगड़ा-झगड़ा होता है। लेकिन वे एक-दूसरे से स्नेह भी उतना ही करते हैं। बहन की अनुपस्थिति में भाई उसके लिए चीजें संभाल कर रखता है और बहन, भाई के लिए। लेकिन छोटी-छोटी बातों पर रूठना, झगड़ना भी होता रहता है। उम्र बढ़ने के साथ यह रगड़ा-झगड़ा कम होने लगता है तो उनके रिश्ते में आत्मीयता का भाव आ जाता है। भाइयों के लिए बड़ी बहनें मां की तरह हो जाती हैं, छोटे भाई के अभिभावक की भूमिका अदा करने लगती हैं। अगर भाई बड़ा है तो वह पिता की भूमिका निभाता है। छोटी बहन की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। भाई-बहन के रिश्ते में कई रिश्तों की मिठास बसती है, तभी तो बात-बात में चिढ़ाने वाली बहन, ससुराल विदा होते वक्त भाइयों को रुला देती है।

भरोसे का बंधन

रक्षा बंधन का पर्व, हर बहन के लिए अपने भाइयों के प्रति स्नेहमयी जुड़ाव को जताने का सबसे बड़ा अवसर होता है। कलाई पर बंधी राखी मात्र रेशमी धागा नहीं, भाई के प्रति बहन का भरोसा होता है। भरोसा कि कितना भी दूर रहें लेकिन भाई उसे नहीं भुलाएगा। उसकी हर खुशी में शामिल होगा, संकट के समय उसकी मदद के लिए आ खड़ा होगा। इस भरोसे से उन्हें संबल मिलता है, इसके बल पर बहनें हमेशा खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं।

समय के साथ बदला रिश्ता

सच है कि सारे रिश्ते-नातों की तरह भाई-बहन के रिश्ते में भी बदलाव हुए हैं। ये बदलाव सुखद और सलोने हैं। आज भाई, बहन दोस्तों की तरह रहते हैं। उनके रिश्ते में एक खुलापन आया है। वे अपने करियर और जीवन से जुड़ी बहुत सी बातें एक-दूसरे से बेझिझक साझा करते हैं। ऐसी बातें, जो मां-पिता से कहने में हिचकते हैं। भाई अब अपनी बहनों को खुद से कमतर नहीं मानते हैं। इसीलिए बहन के लिए भाई के मन में केवल स्नेह नहीं अब सम्मान भी होता है। तभी तो कभी बहन को खाना और पानी के लिए आदेश देने वाला भाई, अब बहन को पढ़ने, आगे बढ़ने में मदद करता है। उससे करियर के बारे में डिस्कशन करता है। स्वेच्छा से संपत्ति में हिस्सेदारी देता है। विवाह के बाद भी बहनें अपने परिवार का हिस्सा हैं, नए जमाने में इस नई अवधारणा और सोच ने भाई के लिए बहन के प्रेम को कई गुना और बढ़ाया है। तभी तो राखी पर बहनों के आने की प्रतीक्षा भाई भी करते हैं।

स्वरूप बदला, मायने नहीं

तेजी से आधुनिक हुए समाज के साथ राखी ने भी अपना स्वरूप बदला है। कच्चे सूत से डिजाइनर राखी तक। आशीर्वाद से उपहार तक। लेकिन राखी के मायने नहीं बदले। राखी अब भी रिश्तों में मिठास और अपनापन बनाए रखने का माध्यम है। प्रेम-स्नेह और आत्मीयता का बंधन समय के साथ और भी प्रगाढ़ हो, राखी यही संदेश देती है। a

संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

भाई की राशि के अनुसार इस रंग की राखी बांधें, मिटेंगे रोग, होगा बड़ा लाभ

मेष : इस राशि के लोगों के लिए लाल रंग की राखी उपयुक्त रहेगी। **वृषभ :** इस राशि के भाइयों की कलाई पर नीली राखी बांधनी चाहिए। **मिथुन :** इस राशि के भाइयों को कलाई पर हरी राखी बांधनी चाहिए। **कर्क :** इस राशि के भाइयों की कलाई पर सफेद रंग की राखी बांधनी चाहिए। **सिंह :** इस राशि के भाइयों की कलाई पर लाल या पीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। **कन्या :** इस राशि के भाइयों की कलाई पर गहरे हरे रंग की राखी बांधनी चाहिए। **तुला :** इस राशि के भाइयों की कलाई पर गुलाबी रंग की राखी बांधें। **वृश्चिक :** इस राशि के भाइयों की कलाई पर बहनों को लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए। **धनु :** इस राशि के भाईयों को पीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। **मकर :** इस राशि के भाईयों को नीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। **कुंभ :** इस राशि के भाई की कलाई पर गहरे हरे रंग की राखी बांधनी चाहिए। **मीन :** इस राशि के भाईयों को पीली राखी बांधनी चाहिए।

एसआईपी एकेडमी ने भारत में 1000 से भी ज्यादा गरीब बच्चों को शैक्षणिक सहयोग देने की घोषणा की

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

एसआईपी एकेडमी ने गरीब बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिये आज सामाजिक प्रभाव वाली पहलों की घोषणा की। उन्होंने बच्चों की मदद करने के महत्व पर जोर दिया, खासकर उनकी जो कि गरीब पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार, इस महामारी ने चुनौती को और भी ज्यादा कठिन बना दिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर, दिनेश विक्टर ने भारत में एसआईपी एकेडमी के परिचालन की 19वीं वर्षगांठ के मौके पर यह घोषणा की। एसआईपी फाउंडेशन के माध्यम से, यह संस्थान भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों में कौशल विकास के लिये कई पहलों को सहयोग दे रहा है। एसआईपी फाउंडेशन के माध्यम से यह संस्थान भारत में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों में कौशल विकास के लिये कई सारी पहलों को सहयोग दे रहा है।

दिनेश विक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर-एसआईपी एकेडमी इंडिया का कहना है कि एक संस्थान के रूप में यह बच्चों में अपने कार्यक्रमों एसआईपी एबेकस भारत के प्रमुख एबेकस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ग्लोबलकार्ट भारत के प्रमुख क्रिएटिव आर्ट ट्रेनिंग सेंटर्स और माइकिड्स एक अनूठा स्कूल आधारित अंग्रेजी भाषा प्रोग्राम के माध्यम से जीवन कौशल विकसित करने का काम कर रहा है। एसआईपी एकेडमी बच्चों और स्कूलों को सीखने के उस अंतर को भरने में मदद करने और संख्यात्मकता, साक्षरता और बच्चों की रचनात्मक क्षमताओं का एक मजबूत आधार तैयार करने में एक अनोखी स्थिति में था।' इस मौके पर अपनी बात रखते हुए, दिनेश विक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एसआईपी एकेडमी ने बच्चों को सॉफ्ट स्किल सिखाने के महत्व पर जोर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने सामाजिक पहलों के बारे में जागरूकता और संवेदना बढ़ाने की जरूरत का उल्लेख किया।

उन्होंने आगे बच्चों की मानसिक क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के दृष्टिकोण पर जोर दिया- ताकि युवा और बच्चे, विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से कौशल अर्जित करें, जिनका वे हिस्सा हैं । साथ ही एसआईपी एकेडमी प्रोग्राम में जीवन कौशल सीखें। भारत भर में एसआईपी एकेडमी कार्यक्रमों के तहत कुल 148 एसआईपी स्टूडेंट्स, जिन्होंने महामारी के दौरान कमाई करनेवाले माता-पिता को खो दिया, उन्हें 12 महीने के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये उनकी मासिक फीस में शुल्क माफी की पेशकश की जा रही है। इसके अलावा, वंचित वर्गों के 225 बच्चों को 75ङ्ग तक शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। यह सहायता भारत भर के 45 एसआईपी एबेकस केंद्रों में 15 से अधिक राज्यों में उपलब्ध है।

रॉयल एनफील्ड ने नया और स्टाइलिश हंटर 350 लॉन्च किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मिड-साइज़ मोटरसाइकिल सेगमेंट में ग्लोबल लीडर रॉयल एनफील्ड ने आज मोटरसाइकिल का दो-पहिया डबल-एस्प्रेसो नया हंटर 350 लॉन्च किया शहरी हलचल के लिए डिज़ाइन किया गया नया हंटर 350 एक रीमिक्स्ड रोडस्टर है जिसमें रॉयल एनफील्ड के चरित्र को एक स्टाइलिश कॉम्पैक्ट और मस्कुलर डिज़ाइन के साथ फिर से जोड़ा गया है। जो भीड़-भाड़ वाली शहर की सड़कों उपनगरीय बैकरोड और उससे आगे एंप्लॉम्ब से निपट सकता है।

हंटर 350 के पीछे की प्रेरणा के बारे में बात करते हुए आयशर मोटर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ लाल ने कहा रॉयल एनफील्ड में हम अपने उपभोक्ताओं और समुदाय के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं उनकी इच्छाएं और आकांक्षाएं हमारे द्वारा बनाई गई मोटरसाइकिलों को आकार देती हैं और हम हमेशा उनके लिए नए अनुभव और शुद्ध मोटरसाइकिलिंग के नए प्रारूप तैयार करना चाहते हैं हमेशा उत्साही मोटरसाइकिल चालकों का एक समूह था जो हमारे ब्रांड से प्यार करता था लेकिन हमारे पोर्टफोलियो के भीतर सही तरह का रवैया नहीं मिला हंटर 350 उनके लिए है यह एक मोटरसाइकिल है जो अलग-अलग प्रजातियों की ताकत को जोड़ती है और इसे एक सुपर स्टाइलिश और मजेदार पैकेज में एक साथ लाती है जो कि अचूक रॉयल एनफील्ड चरित्र के साथ शुद्ध मोटरसाइकिलिंग का एक नया स्वाद है

हंटर 350 के लॉन्च पर बोलते करते हुए रॉयल एनफील्ड के सीईओ बी गोविंदराजन ने कहा हंटर 350 दुनिया भर से कई वर्षों की अंतर्दृष्टि एकत्र करने और उपभोक्ता अध्ययन का परिणाम है यह एक मोटरसाइकिल है जो बड़े महानगरों में घर जैसा महसूस करती है और अनुभवी सवार के लिए रोमांचक है और एक नए सवार के लिए आसान और सुलभ है इसका छोटा व्हीलबेस अधिक कॉम्पैक्ट ज्योमेट्री और हल्का वजन इसे शहरी संदर्भ में बहुत फुर्तीला और युद्धाभ्यास बनाता है हमें पूरा विश्वास है कि यह नया रोडस्टर पूरी तरह से वैश्विक उपभोक्ताओं के हमारे शुद्ध मोटरसाइकिलिंग की दुनिया में प्रवेश करेगा आवाज़, रंग, स्टाइलिंग, हैंडलिंग, प्रदर्शन फ्लीट-फुट हंटर 350 के बारे में सब कुछ आपको किसी अन्य की तरह एक अनुभव के साथ जगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

रॉयल एनफील्ड के डिजाइन प्रमुख मार्क वेल्स ने कहा रॉयल एनफील्ड के लिए एक मजेदार हल्का और अधिक चुस्त 350 रोडस्टर विकसित करना दुनिया में सबसे स्वाभाविक बात लग रही थी यह ताजा है लेकिन अभी भी पूरी तरह से रॉयल एनफील्ड है हर बार जब मैं इसे देखता हूं, हंटर मुझे एक लापरवाह एहसास देता है युवा होने का, मेरी बाइक पर कूदने और साथियों से मिलने के लिए चक्कर लगाने का। ' हंटर 350 रॉयल एनफील्ड लाइन-अप के भीतर विशिष्ट रूप से अद्वितीय है। पुरस्कार विजेता 350 सीसी जे-सीरीज़ प्लेटफॉर्म पर निर्मित, अत्यधिक फ्लिकेबल हैरिस परफॉर्मेंस चेसिस के साथ, हंटर शहर की सड़कों पर नाजुकता के बिना, मुस्कराहट का आनंद देता है।

हंटर 350 के साथ आप मज़ेदार, स्पर्शनीय मोटरसाइकिल को लेने के एहसास और अपने पुराने स्कूल एनालॉग के साथ नए युग के वाइब्स को पूरा करेंगे। इसे चलाने के साथ ही आपको एक आकर्षक इनतइसम का एहसास होगा, जो तेज होने पर एक शानदार सवारी का आनंद में बदल जाता है। इसकी कॉम्पैक्ट ज्योमेट्री, फुर्तीला स्टीयरिंग और आत्मविश्वास से भरी ब्रेकिंग की बदौलत भीड़-भाड़ वाली सड़कों से गुजरना। इसे शहर की सीमा से आगे ले जाएं और यह रीमिक्स रोडस्टर चौड़े अलॉय और ट्यूबलेस टायर्स पर स्ट्रेट के साथ-साथ ग्लाइड होगा। फिर, इसे मोड़ और मोड़ में कोण दें और इसकी फर्म और अल्ट्रा-रेस्पॉन्सिव चेसिस और टॉर्की 350सीसी इंजन आपके होश उड़ा देगा।

महाराष्ट्र में इथेनॉल उत्पादन अगले साल 140 करोड़ लीटर तक पहुंचने की संभावनाः चीनी उद्योग

औरंगाबाद। एजेंसी

महाराष्ट्र में इथेनॉल का उत्पादन अगले साल 140 करोड़ लीटर तक पहुंचने की संभावना है। चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों ने यह जानकारी दी। नेशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगवकर ने पीटीआई-भाषा से कहा भविष्य में गन्ने से संबंधित ईंधन की मांग भोजन से अधिक होगी। उन्होंने कहा, ''इसलिए, महाराष्ट्र में चीनी उद्योग को आने वाले समय में ऊर्जा उद्योग भी कहा जाएगा।'' इथेनॉल चीनी मिलों का उप-उत्पाद है। इसका उत्पादन चक्र एक दिसंबर से 30 नवंबर तक है। राज्य सहकारी चीनी मिल संघ के एक प्रतिनिधि के अनुसार, 2020-21 में महाराष्ट्र ने 78 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 100.36 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया। उन्होंने कहा कि राज्य ने दिसंबर 2021 से अब तक 75.88 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया है और इस साल 30 नवंबर तक 85 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 116 करोड़ लीटर तक उत्पादन होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगले साल उत्पादन 130 से 140 करोड़ लीटर तक पहुंच जाने की संभावना है।

एमेज़ॉन इंडिया ने मिलिटरी वेटरंस को समर्पित मिलिटरी टेलेंट पूल वेबसाईट का लॉन्च किया

पूरी दुनिया में 2025 तक 25,000 पूर्व सैनिकों की भर्ती की योजना

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एमेज़ॉन इंडिया ने गर्व के साथ एक समर्पित मिलिटरी टेलेंट पूल वेबसाईट के लॉन्च की घोषणा की। यह वेबसाईट पूर्व सैनिकों और नौकरी बदलने के इच्छुक सैन्य कर्मियों के लिए बनाई गई है। इस वेबसाईट के द्वारा वो एमेज़ॉन इंडिया में काम करने के अवसर तलाश पाएंगे। नौकरी बदलने के इच्छुक सेनाकर्मी, पूर्व सैनिक, रिज़र्व पुलिस बल, या सैनिकों के जीवनसाथी आदि मिलिटरी समुदाय के सदस्य एमेज़ॉन इंडिया के साथ जुड़कर रियल-वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्स टेक्निकल एवं बिज़नेसप्रॉब्लम्स हल करने के अनेक अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

एमेज़ॉन इंडिया ने साल 2019 में मिलिटरी वेटरंस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का लॉन्च किया। यह प्रोग्राम मिलिटरी वेटरंस को काम के अवसर प्रदान करता है। सशस्त्र सेनाओं के वेटरंस संगठन की एक बहुमूल्य संपत्ति होते हैं, जिनके पास विस्तृत ज्ञान एवं कौशल होता है। देश में मिलिटरी वेटरंस को निरंतर काम के अवसर प्रदान करने के लिए एमेज़ॉन इंडिया ऑपरेशंस ने डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसटेलमेंट (डीजीआर), इंडियन नैवल प्लेसमेंट एजेंसी (इन्पा), इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट एजेंसी (आईएएफपीए), और आर्मी वैलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाईज़ेशन (एडब्लूपीओ) के साथ साझेदारी की है। बहुमूल्य अनुभव और अद्वितीय कौशल के साथ मिलिटरी वेटरंस एमेज़ॉन इंडिया में एक विस्तृत टेलेंट पूल सुनिश्चित करेंगे, जो विविधता, समावेशन और समानता के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।

लॉन्च के अवसर पर, तनुजा अबुरी, डीईआई लीडर - एपैक, मिडिल ईस्ट, जीएंडए इंटरनेशनल रिटेल, एमेज़ॉन ने कहा, ''एमेज़ॉन में हमारा यकीन है कि मिलिटरी वेटरंस के पास समृद्ध अनुभव, प्रतिभा और अद्वितीय दृष्टिकोण होता है, जो हमें वृद्धि करने और अपने ग्राहकों की ओर से बेहतरीन परिणाम प्रदान करने में मदद करेगा। इस वेबसाईट के माध्यम से वेटरंस अपनी विशेषज्ञता, योग्यता के क्षेत्रों में अपना करियर आगे बढ़ा सकेंगे और कॉर्पोरेट दुनिया में करियर के उत्तम अवसर प्राप्त कर सकेंगे। हमारे पास विभिन्न ऑपरेशन नेटवर्क में सैकड़ों मिलिटरी वेटरंस लीडरशिप और मैनेजमेंट की भूमिकाओं में काम कर रहे हैं, जिनमें ट्रांसपोर्टेशन, कस्टमर फुलफिलमेंट, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, एवं सुरक्षा ऑपरेशंस आदि शामिल हैं। मिलिटरी वेटरंस को अपने इस सफर में मदद करने के लिए हमारे पास समर्पित रिसोर्स हैं। एफिनिटी ग्रुप ष्ततपवते/।ड्रंवदष् में पूर्व एक्टिव मिलिटरी जवान और एमेज़ॉन कर्मचारी हैं, जो सदस्यों को एक प्रोफेशनल नेटवर्क प्रदान करते हैं, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स का आयोजन करते हैं और एमेज़ॉन के अंदर मिलिटरी वेटरंस को आसानी से नागरिक जीवन में अनुकूलित होने में मदद करते हैं। इसके अलावा एमेज़ॉन का मिलिटरी एम्बेसडर प्रोग्राम (मैप) मिलिटरी वेटरंस की विकास की जरूरतों पर केंद्रित है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए टेलर्ड ट्रेनिंग अनुभव प्रदान करता है।''

अरुण कुमार सिंह, डायरेक्टर, ऑपरेशंस, एमेज़ॉन ने कहा, ''एमेज़ॉन का मिशन दुनिया की सबसे ज्यादा ग्राहक केंद्रित कंपनी बनना है। यह मिशन विविधता एवं समावेशन में हमारे काम पर आधारित है। मिलिटरी वेटरंस विविधता का एक बहुमूल्य हिस्सा हैं; सेना का उनका अनुभव, पीपुल मैनेजमेंट का कौशल, हैंडलिंग की विशेषज्ञता और हार न मानने का दृष्टिकोण एमेज़ॉन को सर्वश्रेष्ठ संगठन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय सेना में सेवाएं देते हुए मैंने देश सेवा के लिए हर रोज चुनौतियों से लड़ना और उनके समाधान तलाशना सीखा है। एमेज़ॉन में भी हम उसी तत्परता से काम करते हैं, हम ग्राहकों के लिए निरंतर इनोवेट करते हैं और उन्हें बेहतर सेवाएं देने के लिए समाधान तलाशते हैं।''

रेकिट किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था और समुदायों की मदद की

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक ताजा और स्वतंत्र रिपोर्ट

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने रेकिट बेंकाइज़र ग्रुप पीएलसी ('रेकिट') द्वारा भारत में किए गए आर्थिक योगदान से जुड़ा अपना स्वतंत्र एनालिसिस प्रकाशित किया है। बता दें कि भारत दुनिया भर में रेकिट के शीर्ष तीन बाजारों में से एक है। हेल्थ, हाइजीन और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के क्षेत्र में दुनिया की दिग्गज कंपनी, रेकिट ने 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कुल 788 करोड़ रुपये (77.5 करोड़ पाउण्ड) का योगदान दिया है। यह रिपोर्ट तीन प्रमुख बिंदुओं पर भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के लिए रेकिट के प्रयासों का आकलन करती है, ये तीन बिंदु हैं 2021 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), रोजगार और सरकारी प्राप्तियां।

उच्च जीडीपी मल्टीप्लायर - रेकिट का जीडीपी मल्टीप्लायर 2.5 है। यह भारत में एक आम कैमिकल एवं फार्मा निर्माता कंपनी की तुलना में लगभग दोगुना है। इसका मतलब है कि 2021 में जीडीपी में रेकिट द्वारा जेनरेट किए गए प्रत्येक 10 लाख रुपये के लिए, कच्चे माल और मजदूरी पर इसके खर्च ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त 15 लाख रुपये की वृद्धि की है।ड2.

सहायक आपूर्ति श्रृंखला - रेकिट की स्थानीय खरीद का 95इ से अधिक भारत के सप्लायर्स से खरीदा जाता है। रोजगार को बढ़ावा - भारत में रेकिट का इंप्लॉयमेंट मल्टीप्लायर 21ड3.है, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग 6 गुना है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के सीईओ एड्रियन कूपर ने कहा, 'हमारी रिसर्च उस बड़े योगदान पर प्रकाश डालती है जो रेकिट जैसी बड़ी और सफल ग्लोबल कंपनी भारतीय अर्थव्यवस्था में कर सकती है; जैसे कि रोजगार के अवसर पैदा करना, पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाना और देश भर में सामाजिक विकास को रफ्तार देना आदि। 'रेकिट ने स्थानीय आबादी को सबसे बेहतर हाइजीन, वेलफेयर और न्यूट्रिशन उपलब्ध कराने के लिए समाज में अपनी पहुंच को और बेहतर बनाने में भी निवेश किया है।'

रिपोर्ट भारत में बड़े पैमाने पर सामाजिक विकास लाने में रेकिट के योगदान के बारे में बात करती है। रिपोर्ट में रेकिट की रिसर्च एवं डेवलपमेंट (आर एंड डी) से जुड़ी पहल, अपने कर्मचारियों के कौशल को और बेहतर बनाने तथा स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान अवसर प्रदान करने की कोशिश करने, और इसके साथ ही स्थानीय समाज को सेहतमंद और स्वच्छ जीवन जीने में मदद करना शामिल है।

रेकिट के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन ने कहा कि: 'हमें भारत में अपनी गहराई तक जमी मजबूत जड़ों और यहां मौजूद दुनिया के सबसे बेहतरीन आरएंडडी एवं आईटी केंद्रों पर बहुत गर्व है। भारत हमारे कारोबार के लिए प्रतिभा का एक बड़ा स्रोत है और स्थानीय सप्लाई चेन हमारी सफलता की अहम कुंजी है। सरकार के 'मेक इन इंडिया' कैम्पेन के अनुरूप, रेकिट की स्थानीय खरीद का 95% भारतीय सप्लायर्स की ओर से आता है।'

रेकिट के दक्षिण एशिया एन्ड्ड गौरव जैन ने कहा कि: 'रेकिट 1934 से भारतीय परिवारों का अभिन्न अंग रहा है। हमें भारत के 75 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में बेहद खुशी हो रही है। ऑक्सफोर्ड का यह स्वतंत्र एनालिसिस भारत में मजबूत विरासत के निर्माण को लेकर हमारी कोशिशों को प्रदर्शित करता है। हम आने वाले वर्षों में भारत के आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों और सामाजिक चुनौतियों को हल करने में मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।' रेकिट सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), इंडस्ट्री एसोसिएशन और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी कर रहा है।

भारत में इसके प्रमुख सोशल इंपेक्ट प्रोग्राम इस प्रकार हैं:

डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैम्पेन, हेल्थ और हाइजीन को लेकर लोगों की आदतों सुधार लाने की दिशा में काम करता है, 2014 में शुरू हुआ यह कैम्पेन 116 मिलियन लोगों तक पहुंचा है। डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम, बच्चों में हाथ धोने जैसी सफाई की आदतें विकसित करता है। यह प्रोग्राम अब तक घर, स्कूल, पास पड़ोस की स्वच्छता, खुद की साफ सफाई और बीमारी के दौरान स्वच्छता जैसे हाईजीन के पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं पर 2 करोड़ बच्चों को शिक्षित कर चुका है।

रीच ईच चाइल्ड प्रोग्राम ने 6,500 बच्चों को मौत और कुपोषण से होने वाली बीमारी से बचाया है। हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज प्रोग्राम, भारत के सफाई कर्मचारियों को आर्थिक रूप से समृद्धि बनाने, इज्जत देने और काम का सुरक्षित माहौल प्रदान करने की दिशा में काम करता है, यह प्रोग्राम अब तक 15,800 से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित कर चुका है।

फ्रैंकलिन टेम्पलटन मप्र में फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (FIBAF) कर रहे हैं लॉन्च

FIBAF का लक्ष्य फ्रैंकलिन टेम्पलटन के इन-हाउस प्रोप्रिटेरी डायनामिक अस्सेस्ट एल्लोकेशन

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

फ्रैंकलिन टेम्पलटन (भारत) मध्य प्रदेश में फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (FIBAF) नामक एक ओपन-एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च कर रहा है। फंड का उद्देश्य इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों तथा निश्चित आय और मुद्रा बाजार उपकरणों के गतिशील रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि और आय का सृजन करना है।

फ्रैंकलिन टेम्पलटन का मानना है कि मध्य प्रदेश में म्यूचुअल फंड के विकास की प्रबल संभावना है, क्योंकि नए निवेशक ट्रेडिशनल अश्योर्ड रिटर्न प्रोडक्ट्स से घटते रिटर्न के बाद निवेश के वैकल्पिक तरीकों को देखते हैं। फंड हाउस मध्य प्रदेश में अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को बढ़ाने को लेकर कार्यरत है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक निवेशकों को म्यूचुअल फंड निवेश के लाभों के बारे में अवगत कराना है। मध्य प्रदेश में म्यूचुअल फंड उद्योग की प्रबंधनाधीन संपत्ति वर्तमान में लगभग 52,000 करोड़ रूपए है, जो इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर सहित अन्य जैसे प्रमुख शहरों में फैली हुई है; और मध्यम से लंबी अवधि में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए तैयार है। FIBAF अपनी निवेश जरूरतों के लिए 'वन-स्टॉप' समाधान चाहने वाले निवेशकों के लिए एक विवेकपूर्ण विकल्प है, क्योंकि यह बाजार मूल्यांकन और मौलिक कारकों-संचालित विचारों के आधार पर इक्विटी और ऋण के बीच सामरिक आवंटन प्रदान करता है। यह प्रोडक्ट उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है, जो न केवल इक्विटी में वृद्धि के अवसरों का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, बल्कि बाजार की अस्थिरता के प्रभाव को कम करना भी पसंद करते हैं। नया फंड ऑफर 16 अगस्त, 2022 को खुलेगा और 30 अगस्त, 2022 को बंद हो जाएगा, जिसके दौरान इकाई 10/- रुपये प्रति इकाई की दर से उपलब्ध होंगी।

फंड के लॉन्च पर बोलते हुए, फ्रैंकलिन टेम्पलटन-इंडिया के अध्यक्ष अविनाश सतवालेकर ने कहा, 'हम एक और विविध निवेश पेशकश लाने के लिए उत्साहित हैं, जो मध्य प्रदेश में जो निवेशकों को बदलते बाजारों के माध्यम से सरल और कुशल तरीके से नेविगेट करने में मदद करता है। हम भारत में विकास के एक नए अध्याय को शुरू करने के लिए उत्सुक हैं, और FIBAF का शुभारंभ इस दिशा में पहला है।

फंड लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, आनंद राधाकृष्णन, प्रबंध निदेशक और मुख्य निवेश अधिकारी - इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी इंडिया, फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने कहा, 'हाल के महीनों में वैश्विक इक्विटी बाजारों में सुधार हुआ है और मुद्रास्फीति, ब्याज दर और चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कई विपरीत परिस्थितियों के बीच अस्थिर बना हुआ है।

टीवी का खर्च कम करने में दर्शकों की मदद के लिए टाटा प्ले का साहसी कदम

■स्टार, सोनी, कलर्स एवं ज़ी के फिल्मों व नाटक के चैनल तथा 203 अन्य चैनल केवल 249 रु. में

■टाटा प्ले (पूर्व में टाटा स्काई) ने अपने सदस्यों के लिए नए किफायती पैक प्रस्तुत किए

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

टाटा प्ले के एमडी एवं सीईओ, हरित नागपाल ने कहा, "मनोरंजन मनुष्य की एक मौलिक जरूरत है। हालाँकि बढ़ती कीमतों के कारण लोग मूलभूत जरूरतों जैसे खाना एवं ईंधन और मन बहलाने के लिए होने वाले खर्च जैसे मनोरंजन के बीच विकल्प चुनने को मजबूर हुए हैं। देश में सबसे बड़े मनोरंजन कार्यक्रम के वितरक के रूप में हमारा दायित्व है कि हम मनोरंजन को किफायती बनाएं।" ये नए पैक एवं इनके मूल्य भारत में सभी मौजूदा व नए ग्राहकों को उपलब्ध हैं। ग्राहक अपने नजदीकी टाटा प्ले विक्रेता के पास जाकर या वेबसाईट www.Tataplay.com द्वारा नए महाबचत वाले पैक ले सकते हैं। मौजूदा सदस्यों को नए 'महाबचत वाले पैक' टाटा प्ले के मोबाईल ऐप में पैक का प्रबंधन करें टैब में मिलेंगे। हिंदी महाबचत पैक में स्टार प्लस, सेट, कलर्स, ज़ी टीवी, स्टार गोल्ड, सोनी मैक्स, ज़ी सिनेमा, कलर्स सिनेप्लेक्स, आज तक, एनडीटीवी, और 203 अन्य चैनल केवल 249 रु. में मिलेंगे।

इन महाबचत करने वाले पैक्स के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए टाटा प्ले ने एक जन अभियान प्रस्तुत किया है, जिसमें हिंदीभाषी बाजारों में करीना कपूर और सैफ अली खान तथा दक्षिण भारत के बाजारों में माधवन और प्रियामणि दिखाई देंगे।

सरकारी बीमा कंपनियों को पांच साल में स्वास्थ्य कारोबार में हुआ 26,364 करोड़ रुपये का नुकसान

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की सभी चार बीमा कमानियों (पीएसयू) को पिछले पांच साल के दौरान स्वास्थ्य बीमा कारोबार में 26,364 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है। संसद में हाल में पेश कैग की एक रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजानिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के स्वास्थ्य बीमा खंड में नुकसान ने अन्य क्षेत्रों के लाभ को घटा दिया है या कुल नुकसान को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान इन चार बीमा कंपनियों.....न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसीएल), ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल) और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) का कुल नुकसान 26,364 करोड़ रुपये था। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लिए स्वास्थ्य बीमा दूसरा सबसे बड़ा कारोबार क्षेत्र है। पहले स्थान पर वाहन बीमा क्षेत्र है। इस क्षेत्र का पिछले पांच साल का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 1,16,551 करोड़ रुपये रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य बीमा कारोबार में सरकारी बीमा कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी निजी कंपनियों की तुलना में लगातार घट रही है। कैग ने कहा कि ऑडिट में यह भी पाया गया कि सार्वजानिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा मंत्रालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया और इन कंपनियों का समूह स्वास्थ्य बीमा खंड में संयुक्त अनुपात 125 से 165 प्रतिशत था। दावों के प्रबंधन के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की आईटी प्रणाली में सत्यापन जांच और नियंत्रण का अभाव है। इससे कामकाज के अलावा रिपोर्ट करने की प्रणाली भी प्रभावित होती हे।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।